



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

15 ज्येष्ठ 1940 (श०)

(सं० पटना 521) पटना, मंगलवार, 5 जून 2018

सं० ३ए-२-वे०पु०-०५/२०१८-४१०९/वि०

वित्त विभाग

संकल्प

4 जून 2018

विषय: बिहार न्यायिक सेवा के पदाधिकारियों को दिनांक: 01/01/2016 के प्रभाव से मूल वेतन पर 30 प्रतिशत अंतरिम राहत की स्वीकृति के संबंध में।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल रिट याचिका सं०-६४३/२०१५ में दिनांक: 27/03/2018 को पारित आदेश के द्वारा सभी राज्यों / केन्द्र शासित प्रदेशों के अधीनस्थ न्यायिक पदाधिकारियों को माननीय न्यायमूर्ति श्री पी. रैकटरामा रेड्डी की अध्यक्षता में गठित द्वितीय राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग की अनुशंसा दिनांक 09/03/2018 के आलोक में वेतन एवं पेंशन पर अन्तरिम राहत प्रदान करने का निदेश दिया गया है।

2. अतः माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक: 27/03/2018 के अनुपालन में राज्य सरकार द्वारा निम्नलिखित निर्णय लिया जाता है:-

- (i) बिहार न्यायिक सेवा के सभी कोटि/ब्रेणी के पदाधिकारियों को मूल वेतन पर 30 प्रतिशत अंतरिम राहत प्रदान किया जायेगा।
- (ii) वेतन में की गयी उक्त बढ़ोतरी पृथक घटक के रूप में मानी जायेगी एवं इस पर कोई मंहगाई भत्ता देय नहीं होगा।
- (iii) उक्त अंतरिम राहत में बकाया (एरियर) की गणना दिनांक 01/01/2016 से की जायेगी।
- (iv) बकाया (एरियर) की गणना द्वितीय राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग के रिपोर्ट के साथ संलग्न एनेकस्चर-१ के आलोक में की जायेगी।

- (v) उक्त अंतरिम राहत के देय बकाया का पूर्ण भुगतान दिनांक 30/06/2018 तक या उसके पूर्व सुनिश्चित किया जायेगा।
- (vi) उपरोक्त प्रकार से अंतरिम राहत के अंतर्गत भुगतान की गयी राशि को रेड्डी वेतन आयोग की अंतिम रिपोर्ट/सिफारिशों के पश्चात् भविष्य में निर्गत होने वाले अंतिम आदेश के अध्याधीन समायोजित किया जायेगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

चहुल सिंह,

सचिव (व्यव) ।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 521-571+10-डी०टी०पी०।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>